

उत्तराखण्ड शासन,
न्याय अनुभाग-1
संख्या- १० C.M/xxxvi(1)/2007-04-चार/2003
देहरादून दिनांक २८ अक्टूबर, 2007

अधिसूचना

मा० उच्चतम न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय हेतु राज्य द्वारा आबद्ध किये जाने वाले विधि अधिकारियों एवं जिला स्तर पर राज्य द्वारा आबद्ध किये जाने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल, फौजदारी एवं राजस्व) अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा नामिका अधिवक्ता आदि को आवधित करते समय शासनादेश संख्या 1144/ कार्मिक 2-2001-53(1)/2001 दिनांक 18-7-2001 द्वारा निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या 07-चार/न्याय विभाग/2003 दिनांक 28 फरवरी, 2003 द्वारा प्रदान की गयी थी।

2. मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-13/2004 (एम०/बी०) नरेन्द्र सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य में दिनांक 14-10-2004 को निम्नाकिंत आदेश पारित किया गया है।—

"It is seen from the writ petition, itself, that thereafter there is another advertisement dated 31-7-2002 for the same post, which has not been challenged. We also fail to see as to how there could be a reservation for a single post, if at all the A.D.G.C was a civil post under the State Government. Even that is not a civil post, which is clear from the judgment of the Supreme Court reported in 2004(4) SCC 714 in the case of State Vs Johrimal, where the post of a public prosecutor has not been held to be a post under the State Government."

3. मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा आबद्ध किये जाने वाले अधिवक्तागण सिविल पद धारण नहीं करते हैं, इन्हें एक निश्चित अवधि के लिये आबद्ध किया जाता है जो व्यावसायिक आवंधन मात्र है व किसी भी पक्ष द्वारा इस आवंधन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। मा० उच्च न्यायालय के उक्त सन्दर्भित आदेश के परिपेक्ष्य में राज्य की लोक सेवाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति, राज्य द्वारा आबद्ध किये जाने वाले अधिवक्तागण के आवंधन पर लागू नहीं होती है।

4. अतः इन परिस्थितियों में अधिसूचना संख्या— 07-चार/न्याय विभाग / 2003 दिनांक 28 फरवरी, 2003 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है

आङ्ग से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,

संख्या—10C.M/o/Y xxxvi(1)/2007-04-चार/2003तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषितः—

- 1— महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
- 2— महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 3— समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- 4— समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 5— विभागीय आदेश पुस्तिका / एन०आई०सी०

स्थिति
(के०पी०पाटनी)
अनुसचिव,